भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3041
30 मार्च, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण कार्यक्रम

3041. श्री अबीर रंजन बिस्वास:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में कितनी सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण होना बाकी है, राज्य-वार और क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार हर क्षेत्र में सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण करने की योजना बना रही है;
- (ग) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण के लिए अब तक कितनी राशि आवंटित की गई है और उक्त राशि में से कितनी राशि का उपयोग कर लिया गया है, तत्संबंधी वर्ष-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सहकारी समितियां डिजिटलीकरण कार्यक्रम में कितनी राशि का योगदान दे रही हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): देश में दो प्रकार की सहकारी संरचनाएं हैं अर्थात् राज्य सहकारी समितियां और बहु-राज्य सहकारी समितियां। केवल एक राज्य में कार्यरत सहकारी समितियां संबंधित राज्य सरकार के कानूनों द्वारा शासित होती हैं और एक से अधिक राज्यों में कार्यरत सहकारी समितियां केंद्रीय कानून, अर्थात् 'बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 के 39) द्वारा शासित होती हैं। उनके प्रशासन से संबंधित किसी भी मुद्दे को संबंधित स्तरों पर निपटाया जाता है। वर्तमान में, सहकारिता मंत्रालय के पास डिजिटल/गैर-डिजिटलीकृत सहकारी समितियों का राज्य-वार और क्षेत्र-वार डेटा केंद्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है।

(ख): सरकार देश में 63000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक परियोजना तैयार कर रही है।

(ग) उपर्युक्त बिन्दु (ख) में वर्णित पैक्स परियोजना के कम्प्यूटरीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में 350 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

(घ) डिजिटलीकरण कार्यक्रम में सहकारिताओं द्वारा योगदान की गई धनराशि का डाटा मंत्रालय के पास केंद्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है।